

ईएसएस डी कालीन उद्यम

बनाम

भारत संघ और अन्य

7 दिसंबर, 1989

[मुख्य न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया, न्यायमूर्ति के. एन. सिंह और

न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल]

*कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952:*  
धारा 1(3)(ए) और अनुसूची 1 खंड (बी)-कालीन बुनाई-क्या "कपड़ा"  
अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है-कालीन निर्माण उद्योग-क्या यह  
अधिनियम के दायरे में आता है।

अपीलार्थी राजस्थान राज्य में कालीन के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करने वाली एक साझेदारी फर्म है। इसके तीन कारखाने हैं। जब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपीलकर्ता फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देने के लिए कदम उठाए, तो अपीलार्थी ने इस आधार पर अधिनियम की प्रयोज्यता का विरोध किया कि वह अधिनियम की अनुसूची I में शामिल कपड़ों का निर्माण नहीं कर रहा था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने माना कि अपीलार्थी द्वारा किए जाने वाले कालीनों के निर्माण

व्यवसाय में वस्त्र शामिल थे और यह कि अधिनियम अपीलार्थी पर लागू होता था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 19ए के तहत केंद्र सरकार से आग्रह किया, जिसने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की और उस अपील को भी खारिज कर दिया गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध है। अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 कालीनों के निर्माण की गतिविधि को आम तौर पर कालीनों के बुनाई के रूप में समझा जाता है और जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में लगा होता है, उसे लोकप्रिय रूप से 'कालीन बुनकर' के नाम से जाना जाता है। बुनाई का अर्थ है करघे पर धागे को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना। इसका अर्थ बुनाई की विधि या रूपरेखा या बुने हुए कपड़े की संरचना भी है। [ 420 बी-सी]

1.2 हालांकि धागे में गाँठे हो सकती हैं, लेकिन अंततः उत्पादित कपड़ा, कपड़ा होना छोड़ नहीं देता है। यह तथ्य कि हस्तशिल्प बोर्ड ने नियमों की आयात व्यापार नियंत्रण नीति नियमावली पुस्तिका के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है कि कालीन हस्तशिल्प का एक उत्पाद है, किसी

भी तरह से मामले में सुधार नहीं करता है, फिर भी कालीन कपड़ा होना समाप्त नहीं कर देता है। वह प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि कालीन बनाने की गतिविधि, हालांकि इसमें गाँठ लगाना शामिल है, सार रूप में, बुनाई के बराबर है और कालीन एक ऐसा कपड़ा है जो बुना हुआ है। इस प्रकार यह "कपड़ा" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आता है जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 1 के स्पष्टीकरण के खंड (डी) में समझाया गया है। [420 डी-एफ]

1.3 इसलिए अनुसूची के 'वस्त्र' को परिभाषित करने के स्पष्टीकरण में गाँठ लगाने का समावेश न किया जाना अप्रासंगिक है। [421 डी]

*पोर्ट्रिट्स स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य*, [1979] 1 एससीआर 545, पर भरोसा किया।

2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार और उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अपीलार्थी की संस्थान अधिनियम के दायरे में आती है और अपीलार्थी सभी मामलों में अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी था। [421 डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1987 की सिविल अपील सं. 1372

राजस्थान उच्च न्यायालय की 1984 की विशेष अपील सं. 336 में दिनांक 29 1. 1986 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए सोली जे. सोराबजी, रोकसेना स्वामी, सुशील कुमार जैन और एल. सी. अग्रवाला।

उत्तरदाताओं के लिए अनिल देव सिंह, हेमंत शर्मा, सी. वी. एस. राव, श्रीमती सुषमा सूरी (एन. पी.) और सुश्री ए. सुभाषिनी (एन. पी.)।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय,

**मुख्य न्यायमूर्ति वेंकटरमैया:**

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कोई प्रतिष्ठान जो कालीन का निर्माण कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1952 (इसके बाद में 1952 के प्रावधान के रूप में संदर्भित) के अधीन है। अपीलार्थी एक एक साझेदारी फर्म है जो राजस्थान राज्य में उससे सम्बन्धित तीन कारखानों में कालीन निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है। जब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देने के लिए कदम उठाए गए तो अपीलार्थी ने इस आधार पर अधिनियम की प्रयोज्यता का विरोध किया कि उसके स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान अधिनियम की अनुसूची I में शामिल 'कपड़े' का निर्माण नहीं कर रहा था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपीलार्थी को सुनने का अवसर देने के बाद 27 जुलाई, 1979 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि उसके द्वारा किए जाने वाले कालीन निर्माण के व्यवसाय के कारण अधिनियम को अपीलार्थी पर

लागू किया क्योंकि कालीन कपड़ा थे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने केंद्र सरकार के समक्ष अधिनियम की धारा 19 ए के तहत एक याचिका दायर की। केंद्र सरकार ने 4 मई, 1981 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी का प्रतिष्ठान 'वस्त्र' के निर्माण में लगा हुआ था और तदनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा गया। इसके बाद अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 1984 के अपने आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने तब उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 29 जनवरी, 1986 को अपील को खारिज कर दिया। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

हमारे समक्ष अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने आग्रह किया गया एकमात्र बिंदु यह है कि जिन उत्पादों, अर्थात्, कालीनों का निर्माण अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है, वे अधिनियम की अनुसूची 1 में वर्णित अभिव्यक्ति 'वस्त्र' के अर्थ में नहीं आते हैं और इसलिए यह अधिनियम लागू नहीं होता। अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (ए) में कहा गया है कि धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन,

अधिनियम प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में लगे हुए कारखाने हैं और जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। अधिनियम की अनुसूची 1 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"निम्नलिखित में से किसी के भी निर्माण में लगा कोई भी उद्योग, अर्थात्:

सीमेंट

सिगरेट

इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद

लोहा और इस्पात

कागज

कपड़ा (पूरी तरह से या सूती या ऊन के हिस्से में बनाया गया या जूट या रेशम, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम.....।"

अधिनियम की अनुसूची 1 में निहित स्पष्टीकरण का खंड(डी) इस प्रकार है:

"(डी) अभिव्यक्ति "वस्त्र" में कार्डींग, कताई, बुनाई, परिष्करण और सूत रंगाई और कपड़े, छपाई, बुनाई और कढ़ाई के उत्पाद शामिल हैं।"

यह विवादित नहीं है कि वह सामग्री जिससे द्वारा कालीन निर्मित किए जाते हैं, ऊन है जो की अनुसूची में उल्लिखित सामग्रियों में से एक है, अर्थात्, पूरी तरह से या आंशिक रूप से कपास या ऊन या जूट या रेशम से बने कपड़े, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम। कालीनों के निर्माण की गतिविधि को आम तौर पर कालीनों के बुनाई के रूप में समझा जाता है और जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में लगा होता है, उसे 'कालीन बुनकर' के रूप में जाना जाता है। बुनाई का अर्थ है करघे पर धागे को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाना। इसका अर्थ बुनाई की विधि या पैटर्न या बुने हुए कपड़े की संरचना भी है। ताना का अर्थ है एक करघे पर लंबाई के हिसाब से व्यवस्थित धागे। जो कपड़ा बुना जाता है, उसमें बाना भी शामिल होता है, जिसका अर्थ है कपड़े की पूरी चौड़ाई में लंबाई के अनुसार बुना गया धागा। इस प्रकार बुनाई की गतिविधि में ताना के माध्यम से बाना को पारित करना शामिल है। ऐसा करते समय भले ही धागे में कोई गाँठ हो, तो भी क्रिया बुनाई ही होती है। केवल इस तथ्य से कि धागे में गाँठे हैं, जो कपड़ा अंततः उत्पादित किया जाता है वह एक कपड़ा, कपड़ा बनना बंद नहीं करता है। यह तथ्य कि हस्तशिल्प बोर्ड ने आयात व्यापार नियंत्रण नीति नियमावली पुस्तिका के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है कि कालीन हस्तशिल्प का एक उत्पाद है, किसी भी तरह से मामले में सुधार नहीं करता है। फिर भी कालीन कपड़ा होना समाप्त नहीं कर देता है। वह प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है क्योंकि हम कालीन बनाने की गतिविधि के बारे

में बहुत स्पष्ट हैं कि हालांकि इसमें गाँठ लगाना शामिल है लेकिन वास्तव में यह बुनाई के समान है और कालीन एक कपड़ा है जो बुना जाता है। इस प्रकार यह अभिव्यक्ति "कपड़ा" के अर्थ के भीतर आता है जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 1 के स्पष्टीकरण के खंड (डी) में समझाया गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि विचाराधीन प्रतिष्ठान अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है।

पोर्ट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, [1979] एस. सी. आर. 545 में इस न्यायालय ने कहा कि 'कपड़े' की अवधारणा एक स्थिर अवधारणा नहीं है। इसमें, नई विकसित होने वाली सामग्रियों, पद्धतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, एक निरंतर विस्तार करने वाली सामग्री और नए प्रकार के कपड़े का आविष्कार किया जा सकता है जो भाषा के साथ कोई हिंसा किए बिना वैध रूप से वस्त्र माना जा सकता है। 'टेक्सटाइल' शब्द लैटिन 'टेक्सेरे' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'बुनाई करना' और इसका मतलब है बुना हुआ कपड़ा। जब धागा, चाहे सूती, रेशम, ऊनी, रेयॉन, नायलॉन या किसी अन्य सामग्री से बना कोई अन्य विवरण से बुने गया कपड़ा जो अस्तित्व में आता है वह एक 'कपड़ा' है और इसी रूप में जाना जाता है। बुनाई का तरीका जो भी हो, बुना हुआ कपड़ा 'कपड़ा' ही होगा। जो आवश्यक है वह धागे के अर्थ से अधिक नहीं है और बुनाई का अर्थ होगा किसी प्रक्रिया के जरिए धागे को



बांधना या एक साथ जोड़ना ताकि कपड़े का निर्माण हो सके। कपड़ा विशेष आकार या मजबूती या वजन का होना आवश्यक नहीं है। यह महत्वहीन है कि इसको किस काम के उपयोग में लिया जाएगा और एक कपड़े के रूप में इसके चरित्र पर असर नहीं डालता है। यह तथ्य की 'ड्रायर फेल्ट्स' का उपयोग कागज निर्माण इकाई में निर्माण की प्रक्रिया में केवल नमी के अवशोषक के रूप में किया जाता है, कपड़े की श्रेणी में आने वाले 'ड्रायर फेल्ट्स' के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो सकता है, अगर अन्यथा वे कपड़ों के विवरण को संतुष्ट करते हों।

इस मामले में हमारे सामने पहले से उद्धृत अन्य निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

इसलिए, 'कपड़े' को परिभाषित करने वाली अनुसूची के स्पष्टीकरण में गाँठ लगाने को शामिल न करना सारहीन है। इस मामले में हमारे सामने कोई और मुद्दा नहीं रखा गया था। इसलिए हम मानते हैं कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार और उच्च न्यायालय यह मानने में सही थे कि अपीलार्थी की संस्था अधिनियम के दायरे में आती है और अपीलार्थी सभी मामलों में अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उत्तरदायी था। अतः अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।